भारत द्वारा छोड़े गये अन्तरिक्ष-यानों की संख्या

700. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अब तक कितने और कब-कब अन्तरिक्ष यान वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु छोड़े है ;

(ख) उनको छोड़ने के उद्देश्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में हमारा अगला कार्यक्रम क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) अभी तक 11 भारतीय अन्तरिक्षयान छोड़े गए हैं, जिनमें से इन्सैट-1ए, 1बी, 1 सी, और 1 डी के अलावा सभी अन्तरिक्षयान स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित किए गए थे। उनके प्रमोचन, मिशन उद्देश्य और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

अन्तरिक्ष यान का नाम	प्रमोचन तिथि	मिशन और उपलब्धियों का ब्यौरा
आर्यभट्ट	19-04-1975	यह प्रथम स्वदेशी प्रौद्योगिकीय उपग्रह था, जिसने उपग्रहों के निर्माण के लिए मूलभूत अवसंरचन और इसके प्रचालन तथा आंकड़ा अभिग्रहण सहित उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्पूर्ण विशेषज्ञता स्थापित की। इस उपग्रह ने अपनी दो वर्ष की मूल निर्धारित कालावधि से अधिक अपने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया ।
भास्कर-I भास्कर-II	07-06-1979 20-11-1981	ये दोनों प्रायोगिक सुदूर उपग्रह थे, जिन्होंने प्राकाशिकी और माइक्रोवेव बैण्डों में भारतीय उपमहद्वीप पर प्रतिबिम्बिकियां प्रदान कीं। इन उपग्रहों ने जलविज्ञान विकी भूविज्ञान और समुद्रविज्ञान से संशोधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान किए । दोनों उपग्रहों ने ढाई वर्ष की निर्धारित कालावधि से अधिक समय तक अपने मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए ।
रोहिणी	18-07-1980 17-04-1983	रोहिणी उपग्रह, हमारे उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस एल० वी -3) से छोड़े गए थे, जिन्होंने सुदूर संवेदन संबंधी प्रयोग करते हुए तथा प्रमोचक रकेटों के मानीटरन से संबंधित अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया ।
एप्पल	19-06-1981	यह स्वदेशी रूप में डिजाइन किया गया प्रथम त्रिअक्षीय भूस्थायी संचार उपग्रह था, जो दो दूरसंचार प्रेषानकरों को ले गया था, जिन्हें ढाई वर्ष से अधिक अपनी मूल निर्धारित कालावधि से काफी अधिक समय तक के लिए विविध संचार और टी वी० प्रयोगों को करने के लिए व्यापक प्रयोग में लाया गया ।

अन्तरिक्ष यान का नाम	प्रमोचन तिथि	मिशन और उपलब्धियों का ब्यौरा
इन्सैट–1ए इन्सैट–1बी इन्सैट–1सी इन्सैट–1डी	08–04–1982 30–08–1983 22–07–1988 12–06–1990	ये चारों प्रचालनात्मक बहु उद्देशीय उपग्रह विदेश से प्राप्त किए गए थे, जिन्होंने राष्ट्रव्यापी आधार पर दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाओं के क्षेत्रों में पूर्ण प्रचालनात्मक सेवा स्थापित की। इनमें से इनसैट–1ए अपने प्रचालन के प्रथम वर्ष में ही असफल हो गया तथा इन्सैट–1सी ने 50 प्रतिशत क्षमता सहित लगभग दो वर्षों तक कार्य किया। इन्सैट–1सी पूरी तरह सफल उपग्रह था और इसने साढ़े सात वर्ष से अधिक समय तक सेवा प्रदान की और इसे अभी भी प्रयोग में लाया जा रहा है। गत वर्ष छोड़ा गया इन्सैट 1डी उपग्रह सम्पूर्ण राष्ट्र को अब उपर्युक्त सेवाएं प्रदान कर रहा है।
आई०आर०एस०–1ए०	17–03–1988	यह प्रथम स्वदेशी प्रचलनात्मक, स्टेट-आफ-दी-आर्ट सुदूर संवेदन उपग्रह है, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए बनाया गया था। यह उपग्रह गत साढ़े तीन वर्षों से, अपनी निर्धारित कालावधि से अधिक समय से कृषि, वानिकी, महासागर-विकास, भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन मत्स्य पालन, परती भूमि का मानचित्रण, सूखा तथा बाढ़ प्रबंध के क्षेत्रों में बहुमूल्य निवेश प्रदान कर रहा है।

(ग) प्रमोचन के लिए आगामी कार्यक्रम निम्न प्रकार है :

अन्तरिक्षयान का नाम	कार्यक्रम
आई०आर०एस०–1बी०	आई आर एस 1–बी उपग्रह, जो कि आई०आर०एस०–1ए के समरूप है, एक स्टेट-आफ-दी-आर्ट सुदूर संवेदन उपग्रह है, जो कि उन सेवाओं को प्रदान करना जारी रखेगा, जिन्हें आई आर एस–1ए से प्राप्त किया जा रहा है। आई आर एस बी1–बी पहले ही प्रमोचन मंच पर हैं और अगस्त 1991 में इसके प्रमोचन की अंतिम तैयारियां की जा रही हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में आई०आर०एस० प्रणाली एक मुख्य घटक बन गई है।
आई०आर०एस०–1ई०	आई०आर०एस०–1ई० को श्रीहरिकोटा से हमारे अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी एस०एल वी०) में रखक 1992 में छोड़े जाने की योजना है।

अन्तरिक्षयान का नाम	कार्यक्रम
श्रोस–सी	विस्तृत रोहिणी उपग्रह (श्रोस) को, स्वदेशी संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए एस०एल वी०) में रखकर इस वर्ष के अन्त तक छोड़े जाने की संभावना है।
इन्सैट–2ए	पांच उपग्रहों वाली द्वितीय पीढ़ी की इन्सैट–II श्रृंखला के उपग्रहों में वह प्रथम उपग्रह है, जिसका देश में निर्माण किया जा रहा है। इन्सैट–II उपग्रहों में इन्सैट–I श्रृंखला के उपग्रहों की तुलना में डेढ़ गुणा अधिक क्षमता है। इन्सैट–2ए को 1992 के प्रारंभ में छोड़े जाने की संभावना है।

Implementation of Indian Broadcasting Programme Service

701. SHRI JAGDSH PRASAD MATHUR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the reasons for delay in the implementation of the Indian Broadcasting Programme Service plan; and

(b) by when it is to be fully implemented and what are its details?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) There has been no delay in the implementation of the Indian Broadcasting (Programme) Service subsequent to the notification on 5[illegible].

(b) Options received from all the Programme personnel have been sent to the U.P.S.C. The allotment of the officers to the four sub-cadres of the Service is to be done by the Screening Committee to be constituted by the U.P.S.C. for implementation of the said Service.

Improvement of infrastructural facilities in rural areas

702. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any proposal is under Government's consideration to improve infrastructural facilities in rural areas of the country in the near future;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the allocations for rural development would be enhanced considerably for the said purpose; and

(d) if so, to what extent the infrastructural facilities would be improved in rural areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) Government recognize the need to improve the infrastructure facilities in rural areas. Under poverty alleviation programmes like Integrated Rural Development Programme (IRDP)/Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and State Sector Minimum Needs Programme (MNP), funds are provided for improving infrastructure facilities in rural areas. The details of action to be taken for further improvement will depend upon funds allocated under the Plan for this purpose.

(c) and (d) As the basic features including the size and shape of the Eighth Five Year Plan are yet to be finalised, information in this regard will be available only after the finalisation of the Eighth Plan.